>

Title: Need to frame guidelines regarding housing and facilities thereof extended to Central Civil servants in the country.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): देश को आजाद हुए 64 वर्ष से अधिक हो गए परंतु आज भी हमारी अनेक व्यवस्थाएं सामंती युग का स्मरण दिलाती है । जिला तथा मंडल मुख्यालयों पर विभिन्न वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के आवास इसके उदाहरण है । अनेक स्थानों पर ये आवास कई एकड़ में फैले हैं। इनमें खेती भी होती है इस खेती तथा अन्य सेवाओं को करने के लिए राजकोष से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी सेवा में रहते हैं जिनकी संख्या 20-25 अथवा 50 तक भी होती है । ये कर्मचारी रजिस्टरों में अपने-अपने कार्यालयों में कार्यरत दिखाये जाते हैं परंतु वास्तव में इन अधिकारियों के यहां कार्य करते हैं । खेती की आमदनी पर बेशक अधिकारी का निजी स्वामित्व होता है । उपरोक्त प्रकार के बंगले तथा वहां प्रचलित राजसी व्यवस्थाएं जहां एक ओर इन अधिकारियों को जनता के सेवक के स्थान पर जनता का मालिक बनाती है वहीं आम आदमी अपनी व्यथा इनके सामने रखने का साहस भी नहीं जुटा पाता ।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि केन्द्रीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों के आवास तथा वहां की व्यवस्थाओं के संबंध में ऐसे मानक निर्धारित किये जायें तथा ऐसे नियम बनाये जायें जो लोकतंत्र की मूल भवना के अनुरूप हों ।